अमृत वाणी

काम की समाप्ति संतोषप्रद हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती।

-कालिदास,

शिक्षाकर्मी कार्य पर लौटे

छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राज्य में विगत 15 दिनों से जारी शिक्षाकर्मियों की हड़ताल अंततः 4 दिसम्बर की मध्यरात्रि समाप्त हो गई। इस दौरान कड़ाके की ठंड के बावजूद जहां शिक्षाकर्मी पहले अपने अपने विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन में जुटे रहे वहीं बाद में हजारों की संख्या में राजधानी पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सरकार द्वारा शिक्षाकर्मियों को रायपुर पहुंचने से रोकने तरह-तरह के उपाय अपनाए गए मगर शिक्षाकर्मियों ने न केवल स्वयं बल्कि सपरिवार वहां पहुंचकर आंदोलन को बरकरार रखा। यहां तक कि उन्हें राजधानी के मैदानों पर अपना प्रदर्शन करने से भी रोका गया और वे एक मैदान से दूसरे मैदान तक भटकते रहे पर अपने आंदोलन को लगातार जारी रखा। हालांकि शासन से मोर्चा के नेताओं की वार्ता भी हुई पर शिक्षाकर्मियों के अपने सभी मांगों की पूर्ति पर अड़े रहने से वार्ता सफल नहीं हो पाई। अंततः शासन ने अपना कड़ा रूख अख्तियार करना शुरू किया। चेतावनी के बाद कई शिक्षाकर्मी बर्खास्त भी किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन की मांग को स्वीकार करना संभव नहीं है। शेष आठ मांगों को मान लिए जाने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी मगर शिक्षाकर्मियों के इस संविलियन की मांग पर अड़े रहने के चलते आंदोलन को इतने दिनों तक चलाया गया। अंततः 4 दिसम्बर की रात्रि शासन से वार्ता के बाद शिक्षाकर्मी सरकार के सख्त रवैये के आगे झुकने को मजबूर हो गए और निशर्त रूप से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।

कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने शिक्षाकर्मियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था लेकिन सरकार द्वारा इस बार अपनाए गए कड़े रूख के चलते इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक कि शासन के दबाव के कारण शिक्षाकर्मियों ने इतने आकस्मिक रूप से आधी रात को अपना आंदोलन वापस ले लिया कि युवक कांग्रेस को शिक्षाकर्मियों के समर्थन में आहूत अपना बंद भी वापस लेना पड़ा।

बहरहाल आंदोलन कितना सफल रहा और आंदोलन पर कितना अंकुश लगा यह तो कमशः शिक्षाकर्मियों और शासन के अपने-अपने आंकलन है, लेकिन इन सबका सबसे अधिक खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा हैं तो वे हैं विद्यार्थी। हालांकि शासन ने अपनी व्यवस्था के द्वारा शिक्षाकर्मियों की कमी पूरी करने का दावा किया है मगर इस दौरान शालाओं में फैली अव्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

जो भी हो, आशा की जानी चाहिए कि काम पर लौटे शिक्षक अब पूरी इमानदारी से अपनी शिक्षकीय धर्म का पालन कर इस नुकसान की यथासंभव भरपाई का प्रयास अवश्य करेंगे।

राजकाज

ओखी से प्रभावित होगा चुनाव

गुजरात विधानसभा का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में चक्रवात तूफान ओखी के गुजरात में दस्तक देने की आशंका मात्र से राजनीतिज्ञों के होश उड़ गए हैं। हद यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की राजुलाए माहुवा और शिहोर में रैलियों को रद्द कर दिया गयाए जबकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रैली भी रद्द कर दी गई। वसुंधरा राजे को माजूरए सूरत में रैली को संबोधित करना था। अब जबकि गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 9 दिसंबर को होना है तो सभी राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार कोई कोर.कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में ओखी की आमद ने इन राजनीतिज्ञों के सारे समीकरण बिगाड़कर रख दिए है। खास बात यह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में ही हैं और वो सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा की चिंता बढ़ना लाजमी है।

अपने ही जब ख़फा होने लगें

महाराष्ट्र के अकोला में किसानों की एक रैली का नेतृत्व कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को गिरफ्तार किया गया और बाद में खानापूर्ति कर उन्हें छोड़ भी कर दिया गया। गौरतलब है कि भाजपा के अंदर ही ऐसे बड़े और कद्दावर नेता मौजूद हैं जो सरकार के काम.काज से खुश नहीं हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम यशवंत सिन्हा का भी है, जिन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का भी विरोध किया और मौजूदा वित्त मंत्री को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसके बाद भी पार्टी और सरकार की ओर से कोई विशेष तवज्जो नहीं मिलने से परेशान यशवंत सिन्हा ने विदर्भ क्षेत्र के किसानों के प्रति सरकार के रवैये का विरोध करने का फैसला लिया और उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। बहरहाल यशवंत जो भी कहें लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं और पहला यह कि यशवंत दुरुखी होकर ऐसा कर रहे हैं और दूसरा यह कि किसान आंदोलन को कोई और नेता न भुना ले इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। बहरहाल अपनों का यूं विरोधी हो जाना अपने आपमें शर्मनाक होता है।

शेखावाटी के परमहंस पण्डित गणेशनारायण

आंजुंझुनू जिले के बुगाला ग्राम में सम्बत 1903 में पौष बदी एकम को गुरुवार के दिन इनका खंडेलवाल ब्राम्हण राजश्यामदास के घर इनका जन्म हुआ। संबत 1917 में मात्र चौदह वर्ष की उम्र में जवलगढ़ के चतुर्भुज की लड़की रायोदा के साथ इनका विवाह सम्पन्न हुआ। जवलगढ़ में ही रह रहे अमीर शाहजादा केशरशाह से इनकी फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। संबत 1947 में ये पिड़ावा नगरी आये। पिड़ावा आगमन के वक्त गणेशनारायण जी पूर्ण अघोरी रूप धारण कर चुके थे।

गणेशनारायण जी भगवती दुर्गा के परमभक्त थे तथा दुगांमंत्र का हर वक्त जाप करते रहते थे। इनके मुंह से उस वक्त जो भी बात निकल जाती वह सत्य होती। यह चमत्कार देख कई लोग इनके परमभक्त बन गये, वहीं कई लोग इनसे डरने लगे क्योंकि ये अनिष्ट घटने वाली घटना का भी पूर्व संकेत कर देते थे, सच्चे साधक होने के उपरान्त भी दुनिया इन्हें पागल मानती थी। ये सदैव लोगों से दूर रहने का प्रयास करते थे।

औरत और बच्चे तो इनसे बहुत डरते थे क्योंकि इनकी वेशभूषा ही ऐसी थी। समाज में बहिष्कृत तथा शास्त्रों में निषिद्ध नीले रंग के वस्त्रों का ही गणेशनारायण जी प्रयोग करते थे। ये सिले हुये कपड़े नहीं पहनते थे। ये कभी श्मशान में लोट लगाते तो कभी पास के भगीलिये जोहड़े में बैठे रहते थे। भोजन करते समय कुत्ते और कौवे भी इनके साथ खाते थे। ये

राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र जो नामी उद्योगपतियों, बहादुर सैनिकों, भित्ति चित्रकला के लिए मशहूर है, वहीं इस क्षेत्र में बड़े-बड़े संत-महात्माओं, फकीर- मौलवियों ने अपनी तपस्या एवं भक्ति के बल पर इस क्षेत्र की पवित्रता बनाये रखने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस श्रृंखला में सिद्ध पुरुष और भविष्यवेत्ता पण्डित गणेश नारायणजी का स्थान सर्वोपरि है। शेखावाटी के परमहंस के नाम से विख्यात गणेशनारायणजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण कम उम्र में ही वेदों, व्याकरण, ज्योतिष में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी शादी शिक्षा पूर्ण होने से पहले हो गयी लेकिन शादी से थोड़े समय बाद ही इन्होंने गृहस्थ से विमुख होकर स्वयं को परमहंस की अवस्था में ढाल लिया तथा नीले वस्त्र धारण करने लगे।

टपकते तथा हंडियों में पड़े चाहे जैसे पदार्थ को पहले गुदा से लगाकर बड़ी खुशी से ग्रहण करते थे। इनकी दृष्टि में किसी भी पदार्थ के प्रति घृणा नहीं थी।

एक बार सेठ जुगलकिशोरजी बिड़ला इन्हें पिलाने ले जाने लगे मगर रास्ते में भगीलिये जोहड़े में आते ही गाड़ी रुक गयी और आगे नहीं बढ़ी। मजबूर होकर बिड़लाजी ने गणेशनारायणजी को वहीं उतार दिया। भगीलिये जोहड़े में पण्डितजी का विशेष स्नेह देखकर इनकी तादगार में बिड़ला ने यहां जोहड़ा खुदवाकर एक घाट बनवाया तथा उस घाट पर एक बहुत ऊँची ''गनेशलाट'' नाम की संबत 1959 में स्तूप बनवाई। इस स्तूप पर चढ़कर देखने से पिड़ावा व पिलानी का पूरा दृश्य साफ दिखाई देता था।

पण्डितजी अपने दर्शनार्थ आये भक्तजनों को प्रश्न करने से पूर्व ही उनके मन की बात बताकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देते थे। इनकी भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं हुई और इन्होंने जिसे भी आशीर्वाद दिया वह धन्य हो गया। पिलानी निवासी सेठ जुगलकिशोर बिड़ला से परमहंस का विशेष स्नेह था तथा इनके आशीर्वाद से ही बिड़ला परिवार उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सका। एक बार पण्डितजी ने कहा कि जुगलकिशोर जा कमाने निकल जा आज तेरा शुभ दिन है। पण्डितजी की आज्ञा मानकर सेठ कलकत्ता की ओर चल दिये। रास्ते में उसे दाहिनी तरफ फन उठाये काला सांप मिला जो शुभ शकुन था मगर सेठ उसे अपशकुन मानकर वापिस लौट आये और पण्डितजी को पूरी घटना बतायी। पण्डित जी बोले जुगलकिशोर तुम से भारी गलती हो गयी यदि चला जाता तो चक्रवर्ती सम्राट बनता। जा अब भी तू राजसची बनेगा। अपनी करनी बरनी बब्द मत होने देना इसे सदैव चालू रखना। बिड़ला परिवार का नाम इसी प्रकार देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिना गया। ऐसी चमत्कार पूर्ण बातों से परमर्सस के प्रति श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ती गयी। इसे भक्तजन देश के सभी भागों में रहते हैं। इनकी मनमौजी स्वभाव के कारण ही लोग इन्हें ''बावलिया'' संत के नाम से भी पुकारते हैं।

महात्मा गणेशनारायणजी से संबत 1969 में पौष मास की नवमी को योग मार्ग द्वारा त्याग दिया। इनके अन्तिम संस्कार स्थल पर एक मन्दिर बना हुआ है जहां इनकी भव्य प्रतिमा स्थापित है तथा पास ही बिड़ला परिवार ने एक ऊंची स्तूप का निर्माण करवा दिया जिस पर संगमरमर की ब्रम्हा, विष्णु, महेश की मूर्तियां लगी हैं। पिड़ावा वासी गणेशनारायणजी को अपना ग्राम देवता मानते हैं। इनकी निर्वाण तिथि पर विशाल मेला लगता है जिसमें हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं।

-रमेश सर्राफ धमोरा,
(ये लेखक के अपने विचार है)

क्या राहुल गांधी लायेंगे कांग्रेस के अच्छे दिन

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पार्टी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। क्योंकि नामांकन के लिए अब तक कोई आवेदन दाखिल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि वे अपनी मां सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी होंगे जो इस पद पर 19 साल से विराजमान हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के साथ ही एक बार फिर राजनीति में वंशवाद और आंतरिक लोकतंत्र पर बहस शुरू हो गई है। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी में एक ही वंश के वर्चस्व को लेकर सियासी दलों सहित आम जनता की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि, भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद का प्रश्न कोई नई बात नहीं है।

एक ओर सवाल उठ रहा है कि नये लोगों को भी आगे आने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए तो वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी है कि कांग्रेस के दारोमदार का सही हकदार कौन है ? हम देखें तो गांधी परिवार अपनी पार्टी व विचारधारा को लेकर प्रारंभ से ही पूर्णतया समर्पित रहा है। भले वे महात्मा गांधी हो या इंदिरा गांधी सभी अपनी हत्या तक पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे है। इस बीच उनके ही वंशज राहुल गांधी को पार्टी की कमान दी जाती है तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

क्योंकि अपने पूर्वजों का पार्टी के प्रति बलिदान उनको ओर भी पार्टी के सन्निकट ले जाने का काम करेगा। पिता की अनुपस्थिति में नौकर से कई गुना अधिक खुद के बेटे द्वारा दुकान के सही चलने के आसार होते है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर से कोई ऐसा नेता वर्तमान में निकलकर बाहर नहीं आया है, जिसने राहुल से बेहतर पार्टी के लिए काम किया हो। अन्य विकल्प के अभाव में राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना उचित प्रतीत होता है। आशा कि जाने चाहिए कि राहुल कांग्रेस को नाजुक दौर से बाहर निकालने के साथ ही पार्टी के अच्छे दिन लायेंगे और वर्तमान राजनीति को एक मजबूत विपक्ष भी देंगे।

बात वंशवाद की है तो किस पार्टी में वंशवाद नहीं है ? किस देश में वंशवाद नहीं है ? एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उसमें तब 15 प्रतिशत सांसद तथा 24 प्रतिशत कैबिनेट मंत्री वंशवादी राजनीति का हिस्सा थे। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार 34 प्रतिशत से अधिक सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

एडीआर आगे कहता है साफ रिकॉर्ड वाले लोगों की तुलना में आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना लगभग दुगनी होती है। अगर बात हम महिला सांसदों कि करें तो 2014 में 11.23 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं किसी ना किसी प्रकार से वंशवादी राजनीति का हिस्सा हैं। आंकड़ा देखें तो 61 में से 29 महिला सांसद ऐसी हैं जिनके परिवार में उनसे पहले कोई ना कोई राजनीति में था, तो वहीं लगभग 8 प्रतिशत महिला सांसदों का ताल्लुक फिल्मी जगत से है। भारत की पहली महिला प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पहली महिला लोकसभा स्पीकर भी इसी वंशवादी राजनीति से ही हमें मिली हैं। मोतीलाल नेहरु से लेकर राहुल गांधी तक, राजनाथ सिंह से लेके पंकज सिंह तक, लालू से लेके तेजस्वी और तेज प्रताप तक, या मुलायम से अखिलेश तक या कश्मीर के फ़ारूक अब्दुल्लाह और उमर अब्दुल्लाह तक, यह फेहरिस्त काफी लम्बी है। राजनीति में वंशवाद केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान में भुट्टो परिवार, नेपाल में कोईराला परिवार, बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया परिवार, श्रीलंका जयवर्धने और भंडारनायके परिवार, अमेरिका में बुश, केनेडी और क्लिंटन वंश का दबदबा चला आ रहा है। 2014 में छपी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 46 प्रतिशत भारतीयों को वंशवादी नेताओं से कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग हर दूसरे भारतीय का कहना था कि वो वंशवादी राजनेता को वोट देना ज्यादा पसंद करते हैं, बनिस्बत किसी गैर वंशवादी नेता के।

असल मयाने में सवाल यह उठना चाहिए कि जिस देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम की हो वहां 60 साल से अधिक उम्र के सांसदों की संख्या आखिर इतनी ज्यादा क्यूं है ? बाकी सरकारी क्षेत्र की तरह चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने की अधिकतम उम्र की समय-सीमा भी तय करनी चाहिए। लोकतन्त्र में वंशवाद तभी सफल और टिकाऊ हो सकता है जब उसके वारिसों में राजनीतिक योग्यता हो। वंशवाद की राजनीति के मुद्दे को उठाने का असली मकसद कुछ भी हो, इसके पीछे की मंशा किसी बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश हो या ना हो, लेकिन सरकार को ये आंकड़े भी जारी करने चाहिए कि जिस लोकसभा क्षेत्र में वंशवादी नेता या सांसद हुए हैं, विकास की गति उस इलाकों में गैर वंशवादी सांसद या नेता के मुकाबले कैसी रही है? आपराधिक मामले और भ्रष्टाचार के मामले किस पर ज्यादा हैं ? तभी हम सही निर्णय पर पहुंच पायेंगे। और इस बात का उचित मूल्यांकन भी कर पायेंगे कि वंशवाद सही है या गलत है।

- देवेंद्रराज सुथार,
(ये लेखक के अपने विचार है)

तुगलकाबाद और दौलताबाद के बीच फंसी एक राजधानी

तुगलकाबाद से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से तुगलकाबाद राजधानी लाने ले जाने जैसी अव्यवहारिक निर्णयों के लिये इतिहास में कुख्यात मोहम्मद बिन तुगलक अगर आज जीवित होता तो देहरादून और गैरसैण के बीच झूल रही उत्तराखण्ड की राजधानी के हस्र को देख जरूर हंस रहा होता। यह हंसने वाली बात ही है क्योंकि गैरसैण भराड़ीसैण में आलीशान विधानसभा भवन बन गया। वहां विधायक निवास और सचिवालय भवन तक बन गया मगर उसे राजधानी का नाम देने से राजनीतिक शासक कतराते रहे हैं। राजनीतिक शासक पहाड़ी राज्य को पहाड़ में राजधानी देने के नाम पर वहां हर साल दो.तीन दिन विधानसभा सत्र का मेला आयोजित कराने के बाद फिर देहरादून में चैन की बंशी बजाते रहे हैं। बात वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी की भी हो रही है मगर सरकार वहां कुछ छोटे मोटे दफ्तार तक नहीं खुलवा पा रही है। राज्य सरकार के इस असमंजस्य के कारण देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन भी अधर में लटक गया है।

मोहम्मद बिन तुगलक केवल एक बार तुगलकाबाद दिल्ली से अपनी राजधानी महाराष्ट्र के देवगिरी या कुतुबाबाद जिसे उसने दौलताबाद का नाम दिया'ए ले गया और अपनी गलती स्वीकार कर राजधानी को वापस दिल्ली याने कि तुगलकाबाद ले आया। मगर उत्तराखण्ड में सन् 2014 से लगातार राजधानी का तामझाम कुछ दिनों के लिये विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून से गैरसैण जा रहा है और एक सप्ताह से भी कम समय वहां गुजार कर सारा लाव लस्कर वापस देहरादून लौट रहा है। राजधानी को केवल विधानसभा के एक सत्र के लिये फुटबॉल बनाये जाने से लगभग 45 हजार करोड़ कर्ज के बोझ तले तथा विकास कार्यों के लिये पूरी तरह केन्द्र की दया पर निर्भर उत्तराखण्ड राज्य के हर साल इस राजनीतिक तमाशे पर करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं।

जब भावनाओं के दबाव में पिछली कांग्रेस सरकार ने सन् 2012 में ही गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित गैरसैण में राजनतिक और शासकीय गतिविधियां शुरू कर दी थीं। गैरसैण में 3 नवम्बर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की ऐतिहासिक बैठक आयोजित हुई। उसके बाद 9 नवम्बर 2013 को गैरसैण के भराड़ीसैण में विधानसभा भवन के लिये भूमि पूजन हुआ। 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैं गैरसैण में विधानभवन का शिलान्यास किया गया। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिह कुंजवाल एवं मुख्यमंत्री ने विधानभवन के साथ ही वहां विधायक ट्रांजिट हॉस्टल अधिकारी ट्रांजिट हॉस्टल तथा कर्मचारी ट्रांजिट हॉस्टल का भी शिलान्यास किया। बाद में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पहली बार गैरसैंण में 9 जून से 12 जून 2014 तक विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र टेंटों में आयोजित हुआ। गैरसैण में 2 नवम्बर 2015 से विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हुआ मगर यह पूरी पांच दिन की अवधि तक चलने के बजाय 3 नवम्बर को ही विपक्षी भाजपा के भारी हंगामें के कारण अनिश्चित् काल के लिये स्थगित हो गया। अगले साल 2016 में 17 एवं 18 नवम्बर को गैरसैण के निकट ही भराड़ीसैण में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में आयोजित हुआ। अब 7 दिसम्बर से भराड़ीसैण में नवनिर्मित विधानभवन में एक और सत्र आहूत होने जा रहा है। अगर राजधानी के नाम पर केवल विधानसभा सत्र आयोजित होने हैं और वहां जनता के कष्टों को दूर करने के लिये स्थाई तौर राजनीतिक शासकों और आला अफसरों ने नहीं बैठना है तो ऐसी केवल तमाशे वाली राजधानी पहाड़वासियों के किस काम की। शिमला की तरह ही गैरसैण को अपनी गतिविधियों के लिये अंग्रेजों ने ही चुना था। सन् 1856 में ब्रिटिश कमिश्नर लुशिंगटन ने गैरसैण के लोहबा में पेशकारी दफ्तर बनाया थाए जिसमें नायब तहसीलदार को रखा गया। उन्होंने इसे सबसे बेहतरीन स्थान बताते हुए प्रशासन का केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी तत्कालीन प्रान्त सरकार को भेजा था तथा सिल्कोट टी स्टेट और अन्य चाय बागानों को मिलकर चाय बगान का मुख्यालय भी बनाया था। इस स्थान की केन्द्रीय स्थिति होने के कारण इसी को पहाड़ी राज्य की राजधानी बनाने की मांग निरन्तर होती रही है मगर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की राजधानियां तो तत्काल तय कर दी मगर गैरसैण की मांग की अनदेखी कर राजधानी के विवाद को चिरस्थाई बना दिया। गैरसैण के निकट भराड़ीसैण में विधानसभा भवनए विधायक निवासए सचिव आवासए उबं अन्य आवश्यक भवनों पर लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इनमें केन्द्र सरकार से शुरू में मिले 80 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। विधानसभा सत्र के दौरान इन भवनों में मंत्रियों, विधायकों, अफसरों और कर्मचारियों के ऐशो आराम के लिये पूरी व्यवस्था है। विधानसभा सत्र के बाद इस प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन राजधानी के आलीशान बंगलों को छतों और बाल्कनियों में बंदरों और लंगूरों की अफ्रातफरी नजर आयेगी। पिछली हरीश रावत सरकार एक बार भराड़ीसैण के भवनों को पर्यटकों के आतिथ्य के लिये पर्यटन विभाग को सौंपने का मन बना चुकी थी, लेकिन तब तक मीडिया में बात खुल जाने से बवाल हो गया। इसी असमंजस के कारण सरकार देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन और अन्य भवनों का निर्माण शुरू नहीं कर पा रही है। सरकार की हिचक इसलिये कि स्थाई राजधानी का उत्तर उसके पास नहीं है। देहरादून की धारक क्षमता राजधानी का बोझ उठाने लायक नहीं थी। कभी देश के कोने कोने से अभिजात्य वर्ग के लोगएए उद्योगपति और चोटी के नौकरशाह रिटायरमेंट के बाद तरोताजा स्वास्थ्य वर्धक आबोहवा और सुरम्यता के साथ ही शान्त माहौल से आकर्षित हो कर देहरादून आकर बसते थे। इसीलिये देहरादून लघु भारत कहा जाता था। लेकिन उस लघु भारत को राजधानी के बोझ ने कुचलकर रख दिया है। राज्य सरकार पर इस बोझ को हल्का करने के लिये भारी दबाव है मगर राजधानी का मसला हल न हो पाने के कारण सरकार बेबस है।

प्रदेश की राजधानी को लेकर दूलमूल रवैये के कारण अगली पिछली सरकारें हर एक काम आधे अधूरे मन से करती रही हैं। भराड़ीसैण में विशालकाय इमारतें तो बन गयीं मगर वहां जाने के लिये सड़कें इतनी तंग हैं कि कई स्थानों पर दो कारें भी एक साथ नहीं गुजर सकतीं।

-जयसिंह रावत,
(ये लेखक के अपने विचार है)